www.vidarbhakibaat.in

Post Reg. No. RNP/NPCITY /169 /2015-2017

प्रखर... मुखर... स्वर

विदर्भ की बात

● वर्ष 17 ● अंक 171 नागपुर, गुरुवार, 18 मई 2017 ● पृष्ठ 8 ● मूल्य ₹ 2

सुप्रभात

अरुणाचल की अंशु ने माउंट एवरेस्ट पर चौथी बार किया फतह

गुवाहाटी

गुवाहाटी (जेएनएन)। अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही 37 वर्षीय अंशु जामसेनपा मंगलवार को चौथी बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने में सफलता हासिल की। दो बच्चों की मां अंशु ने चोटी पर पहुंच राष्ट्रीय ध्वज लहराया जिसे अप्रैल में दलाई लामा ने सौंपा था।

जामसेनपा कर पीआर मैनेजर नंदा किराती दिवान ने बताया कि उन्होंने 13 मई को तड़के 1.45 बजे अपनी चढ़ाई शुरू की थी और मंगलवार सुबह नौ बजे उन्होंने एवरेस्ट पहुंच कर राष्ट्रध्वज फहरा दिया।

इस उपलब्धि को हासिल करने वाली वे पहली भारतीय महिला बन गईं। अगले दस दिनों में वे दुनिया की इस सबसे ऊंची चोटी पर दोहरी चढ़ाई की कोशिश करेंगी और इसके साथ वह पांच बार एवरेस्ट फतह करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगी।

तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने इस साल दो अप्रैल को असम के गुवाहाटी में जामसेनपा को हरी झंडी दिखाकर एवरेस्ट की दोहरी चढ़ाई के लिए रवाना किया था। जामसेनपा ने मई 2011 में दो बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी और उसके बाद उन्होंने 18 मई, 2013 को एवरेस्ट फतह किया था। अगर इस बार वह अपनी दोहरी चढ़ाई में सफल हो जाती हैं, तो वह माउंट एवरेस्ट पर पांच बार चढ़ाई का रिकॉर्ड बना लेंगी।

गूगल इंडिया रिपोर्ट ने जारी किए आंकड़े, भारत में गोवा सबसे ज्यादा दर्शनीय

नई दिल्ली

भारत में गोवा सबसे ज्यादा दर्शनीय पर्यटक स्थल है। गूगल इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि सर्च इंजन पर सबसे ज्यादा बार गोवा के बारे में सवाल पूछे गए। अंतरराष्ट्रीय पर्यटक स्थलों की बात की जाए तो भारत में रहने वाले लोगों को अमेरिका ज्यादा भाता है। गूगल इंडिया रिपोर्ट ने मौजूदा साल में फरवरी से अप्रैल माह के दौरान की गई सर्च के आंकड़े जारी किए हैं।

अंडमान व निकोबार की लोकप्रियता में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। भारतीयों ने इस द्वीप समूह के बारे में जानकारी एकत्र करने में काफी रुचि दिखाई है, जिसकी वजह से इसकी लोकप्रियता में 39.8 फीसद की बढ़ोतरी पहले की अपेक्षा दिखी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो अमेरिका भारतीयों को सबसे ज्यादा लुभा रहा है लेकिन नेपाल, इंडोनेशिया व भूटान को लेकर भी लोगों में उत्सुकता बढ़ रही है। यही वजह है कि नेपाल की लोकप्रियता में 64.8, इंडोनेशिया की 42.1 व भूटान में 40.8 फीसद की बढ़ोतरी देखी जा रही है।

रिपोर्ट बताती है कि महानगरों की अपेक्षा छोटे शहरों के निवासी यात्रा संबंधी जानकारी को लेकर ज्यादा सवाल कर रहे हैं। इनकी तादाद 70 फीसद है जबकि दिल्ली व मुंबई जैसे महानगरों में रहने वाले लोगों में 40.8 फीसद लोग ही इस सिलसिले में सवाल जवाब करते देखे गए हैं। 96 फीसद लोग अपने मोबाइल के जरिये इस तरह के सवाल-जवाब करते हैं।

भारत के टाप तीन पर्यटक स्थल

1. गोवा
2. अंडमान व निकोबार
3. मनाली

सुप्रीम कोर्ट से केंद्र ने कहा, तीन तलाक जब पाप तो इस्लाम के लिए महत्वपूर्ण कैसे

नई दिल्ली

तीन तलाक मामले में बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड से पूछा कि क्या निकाहनामा के समय महिलाओं को तीन तलाक के लिए 'ना' कहने का अधिकार दिया जा सकता है?

सुप्रीम कोर्ट के सवाल

बोर्ड से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्यों नहीं तलाक के लिए एक आधुनिक व आदर्श निकाहनामा बनाया जाए? क्या आप अपने काजी से एक आदर्श निकाहनामा बनाने के लिए कह सकते हैं? नया निकाहनामा तीन तलाक की समस्या भी दूर कर सकता है।

मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड का जवाब

बोर्ड के एक वकील युसूफ मुचला ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बोर्ड की सलाह मानने के लिए सभी काजी बाध्य नहीं हैं। यह भी कहा कि बोर्ड पूरी विनम्रता के साथ सुझावों को स्वीकार करता है और इस पर विचार करेगा।

बोर्ड ने बीते 14 अप्रैल को पास हुआ एक प्रस्ताव भी दिखाया, जिसमें कहा गया है कि तीन तलाक एक पाप है और ऐसा करने वाले शख्स का बहिष्कार करना चाहिए। इस बीच, आपको बता दें कि बोर्ड ने यह भी कहा है कि महिलाएं को भी तीन तलाक का हक है।

राष्ट्रीय महिला आयोग तीन तलाक के खिलाफ

राष्ट्रीय महिला आयोग तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने को तैयार है, लेकिन ऐसा वह तब करेगा जब सुप्रीम कोर्ट उसके लिए उसे नोटिस देगा। यह बात बुधवार को आयोग की सदस्य रेखा शर्मा ने एक सवाल के जवाब में कही। वह तमिलनाडु के इस शहर में महिलाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए पहुंची हैं। रेखा शर्मा ने कहा, महिलाओं के अधिकारों के लिहाज से राष्ट्रीय महिला आयोग मुस्लिमों में लागू तीन तलाक की प्रथा का विरोधी है। इसको खत्म किया जाना चाहिए। इस प्रथा के चलते तमाम महिलाओं को लगातार कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं। इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग चाहता है कि इस प्रथा पर अविलंब रोक लगे। सदस्य ने बताया कि महिलाओं से जुड़े तमाम मामले पुलिस के असहयोग के चलते सुलझ नहीं पाते हैं।

मामला बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदाय का नहीं

वहीं, इस मसले पर केंद्र सरकार की तरफ से एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि यह बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदाय का मामला नहीं है। यह एक अल्पसंख्यक समुदाय जो मुस्लिम है और उस समुदाय की महिलाओं का मामला है। रोहतगी ने यह भी कहा कि अगर बोर्ड तीन तलाक को वैकल्पिक, पाप व अवांछनीय मानता है तो यह इस्लाम का महत्वपूर्ण हिस्सा कैसे हो सकता है। रोहतगी के अनुसार अगर मौजूदा समय में 25 देशों ने तीन तलाक को अमान्य माना हुआ है तो यह इस्लाम का अहम हिस्सा नहीं हो सकता। ■ शेष पृष्ठ 2 पर

भारत-पाक के लिए आज बड़ा दिन

जाधव पर आइसीजे आज सुनाएगा फैसला

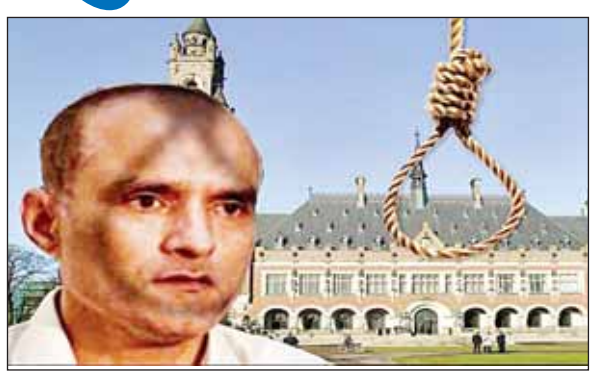

नई दिल्ली

पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आज गुरुवार को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3.30 बजे फैसला सुनाएगा। अदालत ने सोमवार को पाकिस्तान और भारत की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि वह जल्द से जल्द जाधव केस में अपना फैसला सुना देगा।

पाकिस्तान ने कहा- जाधव के पास अपील के हैं 50 दिन

पाकिस्तान ने आइसीजे में सुनवाई के दौरान अपनी दलीलें रखते हुए कहा कि कुलभूषण जाधव को ब्लूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया है और वह इस लायक नहीं है कि उसका कांसुलर एक्सेस दिया जाए। पाकिस्तान ने आगे कहा कि जाधव मामला अंतरराष्ट्रीय अदालत के दायरे में नहीं आता है क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है।

भारत ने कहा- पाक कब जाधव को मार देगा, पता नहीं

जबकि, भारत ने सबसे पहले जिरह करते हुए केस में अपनी तरफ से तथ्यों को सामने रखते हुए कुलभूषण जाधव केस को विएना संधि का सरासर उल्लंघन करार दिया। अब पाकिस्तान जाधव मामले में अपनी दलीलें पेश करेगा। दोनों पक्षों को 90 मिनट का समय दिया गया है।

भारत ने कहा - जाधव पर आरोप 'मनगढ़ंत' और ट्रायल 'हास्यास्पद'

इंटरनेशनल कोर्ट के सामने भारत की तरफ से केस का प्रतिनिधित्व कर रहे दीपक मित्तल ने जाधव पर लगे आरोपों को मनगढ़ंत और पूरी ट्रायल को हास्यास्पद करार दिया। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार सबसे आधारभूत चीज है, लेकिन पाकिस्तान ने जाधव केस में इसकी धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं और जितनी भी बार उससे कांसुलर एक्सेस की मांग की गई, उसने अनसुना कर दिया। उन्होंने कहा कि वियना संधि के तहत कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को पकड़ा जाता है तो दोनों देशों में उसे राजनियक नियमों के तहत मदद मिलेगी, इसका उल्लेख आर्टिकल 36 में भी हुआ है। भारत किसी अन्य देश की न्यायिक व्यवस्था में हस्तेक्षेप नहीं कर रहा है, हम सिर्फ अंतरराष्ट्रीय नियमों की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को नियमों का पालन करना ही होगा।

हरीश साल्वे ने कहा - जाधव को पाक ने किया किडनैप

भारत की तरफ से नीदरलैंड स्थित हेग कोर्ट में जाधव केस की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है कि कहां पर जाधव के लिए दया याचिका लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि पूर्व भारतीय नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव को इरान से किडनैप किया गया और उसके बाद जो उसका कबूलनामा सामने आया वह संदेहास्पद है क्योंकि ये सब पाकिस्तानी सेना की हिरासत में हुआ है।

मानवाधिकार की उड़ीं धज्जियां

हरीश साल्वे ने कहा कि किसी भी केस में मानवाधिकार उसकी बुनियाद होता है, लेकिन जाधव मामले में मानवाधिकार की पाकिस्तान ने धज्जियां उड़ा दीं। हालत ये रही कि मिलिट्री कोर्ट द्वारा ट्रायल के दौरान कुलभूषण को अपने बचाव में वकील देने से मना कर दिया गया। साल्वे ने कहा कि वर्तमान स्थिति बड़ी चिंताजनक हो चुकी है, जिसके चलते भारत ने अंतरराष्ट्रीय अदालत के सामने इस मामले को लेकर इंसाफ की गुहार लगाई है।

आइसीजे में उन्होंने आगे कहा कि भारत ने पाकिस्तान के सामने जाधव के लिए कई बार कांसुलर एक्सेस की मांग की, लेकिन पाकिस्तान ने लगातार भारत की इन मांगों को मानने से इनकार कर दिया।

जाधव के पैरेंट्स के वीजा एप्लीकेशन का नहीं मिला जवाब

हरीश साल्वे ने आगे कहा कि जाधव को अपने बचाव के अधिकार से वंचित किया गया।

जाधव के माता-पिता ने जब पाकिस्तान से वीजा के लिए आवेदन लगाया उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया गया। ■ शेष पृष्ठ 2 पर

केंद्र सरकार का बड़ा कदम, सरकारी मकानों पर कब्जा करने के सारे विकल्प खत्म

नई दिल्ली

सरकारी मकानों पर कब्जा जमाये रखने के सारे विकल्प खत्म कर दिये गये हैं। केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन कर अदालत जाने के भी रास्ते को रोक दिया है। सरकार का यह फैसला माननीय सांसदों व मंत्रियों पर भी लागू होगा।

सरकारी मकानों में निर्धारित समय से अधिक समय तक रहना अब संभव नहीं होगा। सरकारी कर्मचारियों को भी हर हाल में मकान से बेदखल होना पड़ेगा। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को हुआ। सरकारी आवासीय परिसरों को नियत समय पर खाली करना वैधानिक कर दिया गया है। लेकिन जो लोग समय से आवास खाली नहीं करेंगे, उन्हें पहले चरण में भारी जुर्माना अदा करना होगा। इसके लिए भी बहुत कम समय निर्धारित किया गया है। केंद्रीय पूल के मकान सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, सांसद और अन्य कई वर्ग के लिए आरक्षित रहते हैं।

आमतौर पर देखा गया है कि सरकार बदलने के साथ ही सांसदों व मंत्रियों को मकान खाली करना होता है, लेकिन माननीय तरह-तरह के बहाने बनाकर मकानों पर लंबे समय तक काबिज रहते हैं। बार-बार के आग्रह के बावजूद मकान खाली कराना एक बड़ी समस्या हो गई थी।

एनएसजी: चीन को लेकर भारत ने रूस को दी चेतावनी, पहले जैसे नहीं रहेंगे रिश्ते

नई दिल्ली

अंतरराष्ट्रीय संबंध कभी एक जैसे नहीं होते हैं। कोई भी देश स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं हो सकता है। जरूरतें रिश्तों में गर्माहट या तल्खी पैदा करती हैं। ये एक ऐतिहासिक सत्य है कि निर्गुट होने के बावजूद भारत का झुकाव रूस की तरफ रहा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में रूस का बिखरना और अमेरिका का दुनिया के फलक पर बादशाहत कायम करना भी एक सच्चाई है। आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत की मजबूती में अमेरिका अपना भविष्य देखने लगा। इसके साथ ही भारतीय नीति नियंताओं को राष्ट्र विकास में अमेरिका की भूमिका ज्यादा प्रासंगिक लगी। इस परिप्रेक्ष्य में रूस को लगने लगा कि भारत अब उन पुराने रिश्ते को लेकर संजीदा नहीं है, लिहाजा रूस और चीन एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया है कि एनएसजी में सदस्यता के मुद्दे पर रूस को चीन पर दबाव बनाना ही होगा।

रूस-भारत रिश्तों में चढ़ाव-उतार

2000 के बाद सिविल न्यूक्लियर के मुद्दे पर अमेरिका और भारत के बीच करीबी बढ़ी। यही वो दौर था जब रूस को लगने लगा कि अब भारत के साथ उसके रिश्ते ठंडे पड़ रहे हैं। रूस की चिंता के पीछे वाजिब वजह भी थी। कुडनकुलन परमाणु

प्रोजेक्ट पर जिस तेजी से काम होना चाहिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, वहीं परमाणु ऊर्जा के मुद्दे पर भारत की अमेरिका खुल कर तरफदारी करने लगा था। ध्यान देने वाली बात ये है कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अमेरिका और रूस एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। इसके अलावा एनएसजी के मुद्दे पर रूस के रुख से भारत को निराशा हुई। भारत को लगता है कि रूस को जितनी सक्रियता दिखानी चाहिए थी, उसने नहीं दिखाई। चीन की तरफ रूस का झुकाव किसी न किसी रूप में बढ़ा है लिहाजा भारत सरकार रूस को ये संदेश देना चाहती है कि उसे अपनी भूमिका को स्पष्ट करना होगा।

चीन-रूस में बढ़ी नजदीकी

भारतीय नीति निर्माताओं को ऐसा लगता है कि पिछले कुछ समय से रूस और चीन में नजदीकियां बढ़ी हैं। भारत को एनएसजी की सदस्यता दिलवाने में रूस अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है। कहीं न कहीं रूस भी इस बात को समझ रहा है कि चीन के साथ उसकी दोस्ती इस समझौते पर भारी पड़ रही है और भारत इसे टालने की कोशिश कर रहा है।

हाल ही में भारत दौरे पर आये रूस के उपप्रधानमंत्री दिमत्री रोगोजिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन भारत की ओर से इस पर कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। जून में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है। लिहाजा रूस भी मोदी सरकार से रुख से परेशान है।

जानकार की राय

विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मा चेलानी ने बताया कि कूटनीति में सभी देश इस तरह के कदम उठाते हैं। भारत को अपने हितों को सुरक्षित रखने का अधिकार है। ये बात सच है कि चीन की तरफ रूस का झुकाव बढ़ा है, जिसके बाद भारत एक संतुलित कदम उठा रहा है।

एनएसजी में सदस्यता के मुद्दे पर भारत की चिंता जाएज है। भारतीय पक्ष को लगता है कि रूस को जिस तरह से अपनी भूमिका पेश करनी चाहिए वो नहीं कर रहा है। ■ शेष पृष्ठ 2 पर

अरुणाचल प्रदेश में चक्रवाती तूफान से जनजीवन अस्त-व्यस्त, सैकड़ों बेघर

इटानगर

अरुणाचल प्रदेश में चक्रवाती तूफान के साथ हुई तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सोमवार को आई इस प्राकृतिक आपदा में एक की मौत हो चुकी है, वहीं सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार, नमसाई जिले के न्यू मोहोंग में एक बिल्डिंग के गिरने से स्थानीय निवासी खोनिल गोगोई की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसके साथ ही एक आंगनबाड़ी सेंटर के साथ ही एक चर्च को भी काफी क्षति पहुंची है। तूफान ने लगभग डेढ़ घंटे तक तबाही मचाई, जिसमें एक आंगनबाड़ी सेंटर और चर्च के अलावा लगभग 180 घर पूरी तरह से तबाह हो गए। तेज आंधी के कारण फल से लदे सैकड़ों पेड़ और बांस के पेड़ों के जड़ से उखड़ जाने से पावर सप्लाइ लाइन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है।

अब नहीं बचेंगे नक्सली, 'लाल कहर' पर सुरक्षा बलों का कड़ा प्रहार

सुकमा

वामपंथी उग्रवाद को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह के बयान सरकार की तरफ से पहले भी आते रहते थे। लेकिन 24 अप्रैल 2017 को खड़ी दोपहरी में बुरकापाल में नक्सलियों ने हैवानियत का वो खेल खेला जिसमें सीआरपीएफ के 25 जवानों के परिवार उजड़ गए। देश में गुस्सा था और सरकार पर दबाव। गुस्सा, दबाव और जवानों के परिवारों के रुदन के बीच गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब वामपंथी उग्रवादियों की हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उन्होंने कहा कि आठ मई 2017 को नक्सलियों से निपटने के लिए एक समग्र चर्चा करेंगे।

17 मई 2017 को नक्सलियों के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े अभियान(96 घंटे का अभियान) में सुकमा में सुरक्षाबलों ने 20 आतंकियों को मार गिराया। नक्सलियों के खिलाफ इस अभियान में कोबरा बटालियन, एसटीएफ और डीआरजी के 350 जवानों ने

हिस्सा लिया। नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में मणकम केशा, ताती कोसा, कुंजाम बिचोम, रवा देवा माडवी देवा और ओयम हडवा को गिरफ्तार किया गया है।

8 मई 2017 को गृहमंत्री ने नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई जिसमें नक्सलियों से निपटने की रणनीति पर चर्चा की गई।

24 अप्रैल 2017 को सुकमा के बुरकापाल में सीआरपीएफ के 25 जवान हुए शहीद हुए थे। सीआरपीएफ के जवानों पर नक्सलियों पर उस वक्त हमला किया था जब वे दोपहर का भोजन करने के बाद आराम कर रहे थे। शहीद जवान रोड ओपनिंग पार्टी के हिस्सा थे।

नक्सलियों के खिलाफ अभियान की पूरी कहानी

सुकमा में सीआरपीएफ के जवानों की शहादत का बदला ले लिया गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में रविवार से मंगलवार तक चले नक्सल रोधी अभियान में 20 नक्सलियों के मारे जाने का दावा सुरक्षा अधिकारियों ने किया है।

कोबरा बटालियन, एसटीएफ और डीआरजी के संयुक्त अभियान में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सीआरपीएफ का कहना है कि बीजापुर जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र के रायगुंडम के जंगलों में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच कई बार मुठभेड़ हुई। इस संबंध में एक वीडियो भी सामने आया है। इसे उस अभियान के दौरान फिल्माया गया, जो सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन ने नक्सलियों के खिलाफ छेड़ा है।

जानकार की राय

सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई पर यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा कि अगर ये एनकाउंटर सही लोगों का किया गया है तो वो स्वागतयोग्य है। उम्मीद है कि इतनी बड़ी कार्रवाई प्रतिशोध की भावना से नहीं हुई होगी ■ शेष पृष्ठ 2 पर

रक्षामंत्री, सेना प्रमुख के दौरे से पहले एलओसी पर पाकिस्तान की गोलाबारी

जम्मू

जम्मू कश्मीर में रक्षामंत्री अरूण जेटली के पहले दौरे से ठीक पहले पाकिस्तान ने जम्मू संभाग के राजौरी, पुंछ जिलों में भारी गोलाबारी कर सीमांत चौकियों, रिहायशी इलाकों का निशाना बनाया।

रक्षामंत्री अरूण जेटली, सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के साथ बुधवार को राज्य दौरे पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में संघर्ष विराम के उल्लंघन का सिलसिला जारी रखते हुए पाकिस्तान सेना ने पुंछ के बालाकोट सेक्टर में सुबह छह बजे तक 120 एमएम व 82 एमएम के मोर्टार दागे। बालाकोट में गोलीबारी रात को पौने एक बजे से डेढ़ बजे तक जारी रही।

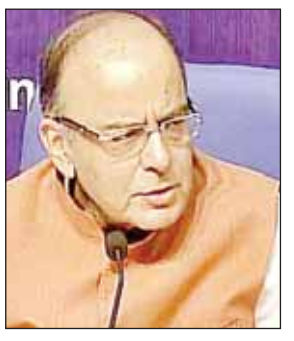

इसके बाद सुबह पांच बजे से छह बजे तक फिर सीमा पार से गोले दागे गए।

पाकिस्तान की ओर से जम्मू के दो सीमांत जिलों में लगातार गोलीबारी से दहशत का माहौल है। राजौरी के नोशहरा व पुंछ के मेंढर में इस समय पाकिस्तान की गोलाबारी के कारण 130 स्कूल एक सप्ताह से बंद हैं।

वहीं राजौरी के नोशहरा में भी पाकिस्तान ने मंगलवार रात को गोलाबारी कर क्षेत्र में दहशत बरकरार रखी।

एक सप्ताह से गोलाबारी में अब तक 3 लोगों की मौत हुई है व 65 के करीब मवेशी मारे गए हैं। क्षेत्र में दस हजार के करीब लोग पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित हैं।

जम्मू के पीआरओ डिफेंस लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष मेहता ने बताया कि भारतीय सेना सीमा पार से हो रही गोलाबारी का कड़ा जवाब दे रही है। देर रात को हुई गोलाबारी से नुकसान के बारे में अभी कोई सूचना नही है।